

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2017—पौष 30, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्र. एफ-ए-3-54-2016-1-पांच (3).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) (जिसे आगे वेट अधिनियम कहा गया है), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 74), मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52, सन् 1976) तथा मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11, सन् 2011) के अधीन अपील की ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जो अपीलीय प्राधिकारी एवं अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर परिक्षेत्र 1/2/भोपाल परिक्षेत्र/जबलपुर परिक्षेत्र/ग्वालियर परिक्षेत्र के समक्ष लंबित हैं और जिन्हें वेट अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबंधों के अधीन दिसम्बर, 2016 से प्रारम्भ होकर दिसम्बर, 2017 तक के कलेण्डर मासों की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है, अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती हैं, और ऐसी कार्यवाहियों को गुण-दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु अपीलीय प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समय-सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ाई जाए;

अतएव, वेट अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ऐसी लंबित अपील कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समयावधि दिनांक 31 मार्च 2018 तक बढ़ाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्र. एफ-ए-3-54-2016-1-पांच (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-54-2016-1-पांच (3), दिनांक 20 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 20th January 2017

No. F-A-3-54-2016-1-V-(3).—WHEREAS, the State Government is satisfied that all such appeal proceedings under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the Vat Act), the Central Sales Tax, 1956 (No. 74 of 1956), the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal ke Pravesh Par kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) and the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Avam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011), which are pending before the Appellate authority and Additional Commissioner, Commercial Tax, Indore Zone-1/2/Bhopal Zone/Jabalpur Zone and Gwalior Zone are to be completed by the end of the calendar months starting from December, 2016 to December, 2017 under the provisions of clause (a) of sub-section (8) of Section 46 of the Vat Act, cannot be completed within the prescribed period, despite all possible efforts being made by the appellate authorities, and that in order to enable the appellate authorities to complete such proceedings on merits, it is necessary to extend the prescribed period up to 31st March, 2018 ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 46 of the Vat Act, the State Government, hereby, extends the period up to 31st March, 2018 for the completion of every such pending appeal proceeding.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.